प्रेषक,

डी०एस० गर्ब्याल, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देघराइन।

शहरी विकास अनुमाग-2

देहरादूनः दिनांक 😵 सितम्बर, 2014

विषय : नगर पंचायत, पुरोला के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पंचायत, पुरोला के पत्रांक—111/लेखा अवस्था0वि0नि 2013—14, दिनांक 21.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पंचायत, पुरोला के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल ₹ 14.09 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, पुरोला के क्षेत्रान्तर्गत संलग्नक—1 में उल्लिखित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु टी०ए०सी० (वित्त विभाग) द्वारा संस्तुत ₹ 13.68 लाख (रूपये तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

 उक्त धनराशि ₹13.68 लाख (रूपये तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, पुरोला को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

. निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में

पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

उ. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप

कराये जायेंगे।

 कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा

उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

. उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है, तो उक्त

स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

9. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी

0. धूनराशि का दिनांक 31-3-2015 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्यों का कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का

विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

..2/-....

2— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—13 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 10.53 लाख, के अनुदान सं0—30 के लेखाशीर्षक—2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191—स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'42 अन्य व्यय के नामे ₹ 2.60 लाख, तथा के अनुदान सं0—31 के लेखाशीर्षक— 2217—शहरी विकास—03—छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—आयोजनागत—191— स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—0191— स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता—03—नगरों का समेकित विकास—05—नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"—'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 0.55 लाख डाला जाएगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/xxvII(2)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी—s.1409130048., s.1409.300050 एवं s.1409.310051. के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

(डी०एस० गर्ब्याल) सचिव।

भवदीय.

## सं0- 1270 (1)/IV(2)-श0वि0-2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
- 3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, नैनीताल।
- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- र्वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
  - 10. अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, पुरोला।
  - 11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12. गार्ड बुक ।

(ओमकार सिंह) उप सचिव।

आश्वा से.

## शासनादेश संख्याः 1270 / IV(2)-श0वि0-47(सा0)-2014, दिनांक सितम्बर, 2014 का संलग्नक।

(घनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	संस्तुत धनराशि
1.	वार्ड नं0 1 में मोटर रोड से सुरेश हिमानी के घर तक सी०सी० सड़क का निर्माण।	1.20
2.	वार्ड नं0 1 में भूपेन्द्र के मकान से गुरूप्रसाद के मकान तक सीसी0 सड़क का	1.24
3.	वार्ड नं0 2 में असवाल के मकान के निकट सुरक्षात्मक कार्य।	1.63
4.	वार्ड नं0 3 में ग0म0वि0नि0 के अतिथि गृह के निकट सड़क का सुरक्षात्मक कार्य।	1.17
5.	वार्ड नं0 4 में एस0सी0पी0 भवन से मोरी रोड़ तक सीसी0 सड़क का निर्माण।	2.01
6.	वार्ड नं0 4 में वर्मा जी के खेत के निकट सीसी0 सड़क एवं सुरक्षात्मक कार्य।	1.07
7.	वार्ड नं0 5 में ठाकुर गुरूजी के भवन के निकट सीसी0 सड़क का निर्माण।	1.16
8.	वार्ड नं0 6 में अरविन्द की दुकान से माता मन्दिर तक इन्टर लॉकिंग कंक्रीट पेबर्स	1.20
9.	वार्ड नं0 6 में सूरज के घर से राजेन्द्र राणा के घर तक सीसी0 1:2:4 खड़िंजा	1.20
10.	वार्ड नं० ७ में असवाल के मकान से मालचन्द नेगी के मकान तक सीसी० सड़क का निर्माण।	1.80
	योग-	13.68

(₹ रूपये तेरह लाख अड़सूठ हजार मात्र)

(ओमकार सिंह) उप सचिव।